मानसिक स्वास्थ्य और लोकतांत्रिक शासन: आधुनिक राजनीति में एक उपेक्षित लेकिन उभरता हुआ विमर्श

डॉ. सुनील कुमार सूरोठिया [1]

[1] **(सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान), राजकीय मॉडल डिग्री कॉलेज पुलवारा बार, ललितपुर (उ.प्र.).**

ABSTRACT:

इक्कीसवीं शताब्दी में मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभर रहा है। वैश्वीकरण, शहरीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली, डिजिटल तनाव और सामाजिक अलगाव ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को व्यापक रूप से बढ़ाया है। इसके बावजूद, लोकतांत्रिक शासन और सार्वजनिक नीति में मानसिक स्वास्थ्य को अब तक अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया है। यह शोध पत्र मानसिक स्वास्थ्य को एक राजनीतिक प्रश्न के रूप में विश्लेषित करता है तथा लोकतांत्रिक शासन, सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। अध्ययन यह तर्क प्रस्तुत करता है कि मानसिक स्वास्थ्य के बिना न तो सक्रिय नागरिकता संभव है और न ही लोकतंत्र की स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है।

KEYWORDS:

मानसिक स्वास्थ्य, लोकतांत्रिक शासन, सार्वजनिक नीति, सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकार, राजनीति।

1. प्रस्तावना

परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान में शासन, सत्ता, संविधान और संस्थाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित रहा है , जबकि नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को निजी या चिकित्सीय विषय मानकर राजनीतिक विमर्श से बाहर रखा गया। किंतु हाल के वर्षों में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का संकट लोकतंत्र की कार्यशीलता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

चिंता, अवसाद, तनाव और आत्महत्या जैसी समस्याएँ केवल व्यक्तिगत नहीं , बल्कि सामाजिक-राजनीतिक संदर्भों से जुड़ी हुई हैं। यह शोध-पत्र इसी संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य और लोकतांत्रिक शासन के बीच के संबंध का विश्लेषण करता है।

2. मानसिक स्वास्थ्य: अवधारणा और सामाजिक संदर्भ

मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक रोगों की अनुपस्थिति नहीं है , बल्कि व्यक्ति की भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक कुशलता का समग्र रूप है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की कार्यक्षमता , निर्णय-क्षमता और सामाजिक सहभागिता को प्रभावित करता है।

राजनीतिक दृष्टि से मानसिक स्वास्थ्य

- सामाजिक असमानता से जुड़ा है
- बेरोजगारी और असुरक्षा से प्रभावित होता है
- सार्वजनिक नीतियों और राज्य की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करता है

3. मानसिक स्वास्थ्य एक राजनीतिक प्रश्न के रूप में

मानसिक स्वास्थ्य को राजनीतिक प्रश्न इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि

- यह सार्वजनिक संसाधनों के वितरण से जुड़ा है
- यह नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रभावित करता है
- यह सामाजिक न्याय और समान अवसरों से संबंधित है

यदि राज्य मानसिक स्वास्थ्य को उपेक्षित करता है, तो वह नागरिकों की मौलिक क्षमताओं को कमजोर करता है।

4. लोकतांत्रिक शासन और मानसिक स्वास्थ्य

लोकतंत्र सक्रिय, जागरूक और संलग्न नागरिकों पर आधारित होता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ:

- राजनीतिक उदासीनता को बढ़ाती हैं
- सार्वजनिक विमर्श में भागीदारी को कम करती हैं
- संस्थाओं पर अविश्वास को गहरा करती हैं

इस प्रकार मानसिक अस्वस्थता लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

5. सामाजिक असमानता और मानसिक स्वास्थ्य

गरीबी, जाति, लिंग और वर्ग आधारित असमानताएँ मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वंचित वर्ग

- अधिक मानसिक तनाव का सामना करते हैं
- स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच रखते हैं
- सामाजिक कलंक का शिकार होते हैं

यह स्थिति मानसिक स्वास्थ्य को सामाजिक न्याय के प्रश्न से जोड़ती है।

6. भारत में मानसिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक नीति

भारत में मानसिक स्वास्थ्य लंबे समय तक नीति-निर्माण का हाशिए का विषय रहा है। हालाँकि हाल के वर्षों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम जैसे प्रयास हुए हैं, फिर भी

- संसाधनों की कमी
- प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव
- सामाजिक जागरूकता की कमी

जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं।

7. समकालीन चुनौतियाँ

आज के समाज में:

- डिजिटल मीडिया का दबाव
- युवाओं में बढ़ता तनाव
- शहरी जीवन की चुनौतियाँ

- महामारी के बाद का मानसिक संकट

मानसिक स्वास्थ्य को एक केंद्रीय राजनीतिक विषय बना रहे हैं।

8. नीतिगत और लोकतांत्रिक समाधान

लोकतांत्रिक शासन को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए

- मानसिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक नीति की प्राथमिकता बनाना
- सार्वभौमिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ
- शिक्षा और कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य समर्थन
- सामाजिक कलंक को समाप्त करने हेतु जागरूकता

ये उपाय लोकतांत्रिक सहभागिता को सुदृढ़ करेंगे।

9. उपसंहार

मानसिक स्वास्थ्य लोकतंत्र का मौन आधार है , जिसे लंबे समय तक राजनीतिक विमर्श में उपेक्षित किया गया। यह शोध -पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ नागरिक ही लोकतंत्र को जीवंत और उत्तरदायी बना सकते हैं।
अतः इक्कीसवीं शताब्दी में लोकतांत्रिक शासन के लिए मानसिक स्वास्थ्य को नीति और राजनीति के केंद्र में लाना अनिवार्य है।

REFERENCES

1. World Health Organization, *Mental Health and Development*.
2. Sen, Amartya, *Development as Freedom*.
3. Wilkinson, Richard & Pickett, *The Spirit Level*.
4. Government of India, *National Mental Health Programme*.
5. भारतीय संविधान, भारत सरकार।
6. UNDP, *Human Development Report*.